

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 2 सितम्बर, 2011

विषय: उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के ट्रांच-2 के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत ट्रांच-2 के कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उत्तराखण्ड, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
3. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेश, टेंडर, कोटेशन विषयक नियमों एवं तदविषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
5. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. यू०य००८०डी००० द्वारा निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट, एग्रीमेंट / ऋण अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और ट्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।

7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे तथा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. निर्माण ऐजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो इसे शासन को अवगत कराकर उक्त तिथि को राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत दिनांक 31-3-2012 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाहय सहायतित योजना-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण-42-अन्य व्यय" की मद के नामे ₹ 158.00 लाख, अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाहय सहायतित योजना-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण-42-अन्य व्यय" की मद के नामे ₹ 36.00 लाख तथा अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-97-वाहय सहायतित योजना-01-नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण-42-अन्य व्यय" की मद के नामे ₹ 6.00 लाख की धनराशि डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 242/XXVII(2)/2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।